HINDUSTAN HINDI N.D. 19/12/2018

संकेत : प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ लग्जरी वस्तुएं ही 28 फीसदी के दायरे में रहेंगी

जरूरी चीजों पर जीएसटी 18% से ज्यादा नहीं: मोदी

मुंबई/नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बात के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, लग्जरी वस्तुओं को छोड़कर जरूरी इस्तेमाल की 99 फीसदी चीजों को 18 फीसदी या इससे कम वाली जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा।

एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उद्यमों के लिए जीएसटी को अधिक से अधिक सरल बनाया जाना जाए। शुरुआती दिनों में जीएसटी को अलग-अलग राज्यों में मौजूद वैट या उत्पाद शुल्क के आधार पर तैयार किया गया था लेकिन समय-समय पर बातचीत के बाद पूरी व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है।

घटाई जाएंगी दरें : सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया कि जीएसटी काउंसिल इसी 22 दिसंबर को होने वाली बैठक में तमाम नए बदलावों पर फैसला कर सकती है। इसमें सीमेंट, कंप्यूटर मॉनिटर और पावर बैंक जैसी चीजों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है। पूर्व में सरकार 191 के करीब वस्तुओं को 28 फीसदी की स्लैब से बाहर कर चुकी है।

व्यापारियों को भी राहत : काउंसिल पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वालों के लिए सिंगल रिटर्न फॉर्म की व्यवस्था का ऐलान भी कर सकती है। साथ ही जीरो रिटर्न वाले कारोबारियों को बिना पेनाल्टी पुराना टैक्स चुकाने का मौका देने पर भी फैसला संभव है। साथ ही ई-वे बिल सिस्टम को आसान और दुरुस्त बनाने के लिए आरएफ टैग के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अब चाहती है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सस्ती दरों के स्लैब में रखा जाए साथ ही कारोबारियों को भी ज्यादा सहूलियतें दी जाएं।

"सभी जरूरी वस्तुओं समेत 99% उत्पादों को जीएसटी के 18% या उससे कम कर स्लैब में रखने की व्यवस्था की जा रही है
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

35 वस्तुएं इस समय जीएसटी के 28% स्लैब में शामिल हैं

22 दिसंबर को जीएसटी परिषद् की बैठक में हो सकता है फैसला

राहत मिलेगी

वाहन औजार व कलपुर्जे, टायर, मोटर वाहन पर घटेगा कर
सीमेंट पर टैक्स घटाकर निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन की तैयारी
कंप्यूटर मॉनीटर, पावर बैंक पर भी घट सकता है जीएसटी

पेट्रोल खर्च घटेगा

देश में मेथनॉल मिले पेट्रोल का परीक्षण शुरू हो गाया है। नीति आयोग को उम्मीद है कि मेथनॉल मिले ईंधन के इस्तेमाल से वाहन चलाने का खर्च पेट्रोल के मुकाबले 10% कम होगा।